ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

भारत एवं चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में नेपाल एवं भूटान की भूमिका

Nepal and Bhutan's Role As A Buffer State between India and China

Paper Submission: 12/02/2021, Date of Acceptance: 21/02/2021, Date of Publication: 22/02/2021

सारांश

एशियाई दिग्गज भारत और चीन क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर दबदबा बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहे है। भूटान और नेपाल के साथ भारत का सदियों पुराने संबंध है। भूटान–नेपाल ऐसे दो पड़ोसी देश है जिनका भारत के साथ सामरिक एवं रणनीतिक संबंध एक परम्परा के रूप में स्वतंत्रता के समय से चले आ रहे हैं। भारत को घेरने की रणनीति के तहत चीन अपनी राजनीतिक चालों से हमें मात देने के निरन्तर प्रयास कर रहा है, चीन अपना प्रभुत्व बफर स्टेट में बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास में भारी निवेश कर रहा है, ताकि भारतीय सीमाओं तक अपनी आसान पहुँच बना सके। वर्तमान में भारतीय रक्षात्मक दृष्टि से भूटान और नेपाल का गुणात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है, जिस प्रकार चीन अपनी 'चैकबुक' नीति अपनाकर जो हस्तक्षेप कर रहा है वह इन देशों की आन्तरिक समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। बदलते वैश्विक परिवेश एवं बनते नये सामरिक समीकरणों को दृष्टि में रखते हुए इन राष्ट्रों के प्रति व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

Asian giants India and China have been striving to dominate at the regional and global level. India has a centuries-old relationship with Bhutan and Nepal. Bhutan-Nepal are two neighboring countries whose strategic and strategic relations with India have been a tradition since the time of independence. As a strategy to encircle India, China is constantly trying to beat us with its political moves, China is investing heavily in the development of infrastructures to increase its dominance in the buffer state, so that it can have easy access to Indian borders Could. Currently, Bhutan and Nepal are of great importance from the Indian defensive point of view, just as the intervention that China is taking by adopting its 'checkbook' policy, the direct impact of the internal problems of these countries also affects our security system. There is a need to formulate a comprehensive strategy towards these nations keeping in view the changing global environment and the new strategic equations being formed.

मुख्य शब्द : अन्तस्थ, आयुद्ध, स्वायतशासी, माओवाद, बी.आर.आई, ड्रेयुला।
Antastha, Ayudha, Autonomous, Maoism, BRI, Dreula.

विकास शर्मा
पूर्व शोधार्थी,
रक्षा, स्त्रॉतेजिक एवं भू राजनीतिक अध्ययन विभाग,
हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल
उत्तराखण्ड, भारत

भारती चौहान
प्रोफेसर
रक्षा, स्त्रॉतेजिक एवं भू राजनीतिक अध्ययन विभाग,
हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखण्ड
भारत

प्रस्तावना

दो परस्पर शत्रु राष्ट्रों के मध्य स्थित अन्तस्थया बफर राष्ट्र का महत्व अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। अन्तस्थ राष्ट्र के अस्तित्व के कारण ही वे शत्रु देश के युद्ध से पृथक रह पाते थे बफर राष्ट्र की नीति का उपयोग ब्रिटिश शासकों द्वारा 1764 से 1881 तक प्रबल रूप से किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के कारण किसी भी राष्ट्र का तटस्थ रहना असंभव हो गया है। नेपाल राष्ट्र हिमालय के दक्षिण ढलान पर भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। दो पड़ोसियों के मध्य घिरा नेपाल एक और मध्यवर्ती (बफर स्टेट) तथा दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व का क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल गंगा के मैदानों के लिए उतरी द्वार है और इसी कारण से भारतीय सुरक्षा व्यवस्था व स्थायित्व नेपाल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।[1]

हिमालय की गोद में स्थित नेपाल और भारत का संबंध कुछ अपराधों को छोड़कर प्रायः मैत्रीपूर्ण रहा है क्योंकि आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के निकट है।[2] नेपाल की पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई लगभग 840 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल 14,7181 वर्ग किलोमीटर है। हिन्दुओं ने नेपाल को अपने 'पूजा–स्थल' तथा नेपालियों ने भारत को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के रूप में देखा है।

प्राचीन काल में नेपाल भारत और तिब्बत के मध्य व्यापार की एक कड़ी रहा है यही कारण है कि भारत एवं नेपाल के संबंध अतीत काल से बहुत घनिष्ठ रहे हैं किंतु चीन नेपाल में अपना नया आयुध केंद्र बनाने की कार्रवाई कर रहा है जिससे दोनों देशों में मनमुटाव के साथ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रही है।[3] क्योंकि नेपाल की कुल 850 किलोमीटर से अधिक सीमा दक्षिण–पूर्व एवं पश्चिम में भारत के 5 राज्यों क्रमशः सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तथा उत्तराखंड से मिलती है तथा उत्तरी सीमा चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत से मिलती है।[4]

भारत के लिए नेपाल का महत्व

नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 'पहले पड़ोस की नीति' के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में एक था जबकि इससे पहले आखरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।

1. वर्तमान सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं जैसे कृषि रेलवे संबंध और अतंर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास सहित द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है।
2. बिहार के रक्सौल और काठमांडु के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के अमेलखगंज आज तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी सहमति बनी है।
3. नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है और भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता भी माना जाता है।
4. दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कुछ विशेष प्रतिबंध नहीं रहा है सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत–नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है।
5. रक्षा सहयोग के क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है।
6. भारतवर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है।
7. नेपाल की सेना के आधुनिकरण करने के लिए भारतीय सेना हमेशा से ही साथ प्रयासरत रही है।
8. नेपाल का सामरिक महत्व भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

भारत–नेपाल शांति और मित्रता संधि

स्वतंत्र भारत ने नेपाल को एक स्वतंत्र प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और दो सम्प्रभु राष्ट्रों के बीच 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच भारत मित्रता संधि संपन्न हुई जो दोनों राष्ट्रों के मध्य विशेष संबंध का आधार स्तंभ है। जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनीष्ट, रणनीतिक संबंध स्थापित करना है तथा दोनों देशों के बीच और लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है साथ ही नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा प्रदान करती है इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू–आबद्ध देश होने के कारण कई विशेषाधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।[6]

नेपाल के साथ भारत की जोड़ी सुरक्षा आवश्यकता का उल्लेख करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि ''जहां तक एशिया में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों का प्रश्न है, इस संदर्भ में भारत व नेपाल के हित समान है। यद्यपि दोनों देशों के मध्य कोई सैनिक सन्धि नहीं है, परंतु फिर भी भारतीय सरकार नेपाल पर किसी और से होने वाले आक्रमण को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेगी। नेपाल पर हुआ आक्रमण भारत को अपनी सुरक्षा के लिए संकट मानेगा।''[7]

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान समय में वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न समस्याओं से जूझ रहे राष्ट्रों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, वहीं पड़ोसी राष्ट्र चीन अपने नापाक इरादों से अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर अपनी गतिविधियों का जाल फैला रहा है। हिमालय राज्य नेपाल एवं भूटान पर यह प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। चीन की दक्षिण एशिया में सर्वोच्च बनने के दूरगामी परिणाम इन छोटे राष्ट्रों में व्यापक चीनी प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल भारत से दूरी बनाकर नित्य नई समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। हिमालय राष्ट्र भूटान में निरंतर घुसपैठ के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है। अतः भारतीय सरकार को अपनी क्षमताओं और प्रभाव में वृद्धि करते हुए उचित अवसरों को भुनाना होगा।

चीन की नेपाल नीति

वर्ष 1970 में नेपाल के शासक राजा वीरेन्द्र द्वारा नेपाल को भारत और चीन के बीच 'शांति क्षेत्र' के रूप में चिह्नित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने अधिक रूचि नहीं दिखाई जबकि चीन द्वारा इसका समर्थन किया गया भारत–नेपाल संबंधों में वर्ष 2015 में एक नया मोड़ तब आया जब भारत ने नेपाल पर अनौपचारिक परंतु प्रभावी नाकाबंदी की जिसके कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई चीन ने इसका लाभ उठाकर तिब्बत में

नेपाल से लगी अपनी सीमा खोल दी चीनी राष्ट्रपति नेपाल यात्रा के बाद नेपाल ने 'वन चाइना पॉलिसी' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसी भी सेना को चीन के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति ना देने का वादा किया है।[8] चीन पिछले कुछ समय से नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार होने के भारत के दर्जे को हथियाने के लिए बढ़–चढ़कर प्रयास कर रहा है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से दक्षिण एशियाई ही देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। चीन भारत की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा को रोकना चाहता है जो कि भविष्य में चीन को एक महाशक्ति बनने के मार्ग में बाधा बन सकता है। तिब्बत में भारत का बढ़ता प्रभाव चीन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है इसलिए दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने और चीन विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु नेपाल के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखना चीन की नेपाल नीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है।[9]

नेपाल चीन रिश्तो का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव

चीन नेपाल के बढ़ते संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इससे माओवाद ड्रग्स अवैध हथियारों की आवाजाही बढ़ने के खतरे हैं चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत नेपाल में अपनी पैठ खो देगा साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है। भारत की नेपाल में भूमिका को अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों ने काफी सराहा था, चीन को लगा कि नेपाल में भारत का हस्तक्षेप सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकता है। अमेरिका द्वारा भारत की भूमिका की सराहना ने भी उसकी इस सोच को और मजबूती दी। इस वजह से चीन ने नेपाल में अपना पूंजी निवेश और प्रभाव दोनों बढ़ाने का रणनीतिक फैसला लिया।[10]

नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हुआ है और चीन ने धीरे–धीरे निवेश और कर्ज देकर उस जगह को भरा है चीन अपने बेल्ट एंड इनीशिएटिव (बी आर आई) में नेपाल को अहम पार्टनर के तौर पर तौर पर देखता है और वैश्विक व्यापार बढ़ाने के अपने बड़े प्लान के उद्देश्य से नेपाल के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है।[11] काठमांडू को ल्हासा बीजिंग रेलवे लाइन से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त नेपाल और तिब्बत में नेपाली सीमा के पास थल बंदरगाह का निर्माण कर रहा है ताकि नेपाल में तेल जैसे आवश्यक सामानों के लिए भारत पर निर्भर न रहना पड़े। वह नेपाल में पनबिजली योजनाएं लगा रहा है तथा चीनी भाषा एवं संस्कृति के केंद्र भी स्थापित करने में जुटा हुआ है नेपाल के माओवादियों से भारत के माओवादियों को भी सह मिलती है इस प्रकार चीन नेपाल रिश्तो के प्रभाव से भारतीय सुरक्षा पर आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियां मिल रही है।[12]

भारत की चिंताएं

चीन और नेपाल के बीच इन समीकरणों को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी 'सुरक्षा कूटनीति' का उपयोग नेपाल के आंतरिक मामलों में कर सकता है। क्योंकि नेपाल भारत के लिए एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना भारत के रणनीतिक हित में नहीं होगा। चीन की मजबूत वित्तीय स्थिति भारत के लिए पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना और चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है।[13] नेपाल में सरकार चाहे कोई भी हो चाहे वैचारिक आधार पर वह चीन के समर्थन में हो या उसके विरोध में वह चीन को नाराज करने की स्थिति में नहीं है चीन नई तकनीक व नई ऊर्जा प्राप्त कर अपनी विस्तारवादी नीतियों और साम्राज्यवादी चेतना को नए सिरे से लागू कर रहा है।[14]

भूटान

दक्षिण एशियाई देशों में भारत जितना बड़ा है भूटान उतना ही छोटा है हिमालय की गोद में बसा यह देश वर्षों से ही शेष दुनिया से अलग–थलग रहा है।[15] हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्मावलम्बी विश्व का एकमात्र देश है भूटान पूरी तरह स्थल रुद्ध तथा भव्य प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न हिमालय देशों में श्रेष्ठतम है भूटान वासियों ने स्वयं ही अपने देश को 'ड्रैयुला' अथवा 'गरजने वाले नाग दैत्य' की भूमि का नाम दिया है तथा शासकों को 'ड्रग ग्यालपा' कहते हैं।

भूटान का क्षेत्रफल 46600 वर्ग किलोमीटर है। दो बड़े राज्यों के मध्य मध्यवर्ती राष्ट्र होने के कारण भूटान की विदेश नीति के समक्ष यह चुनौती रहती है कि कैसे वह अपने पड़ोसियों के साथ रचनात्मक रूप से एवं अपने राष्ट्रीय हितों की उन्नति के अनुसार संबंध बनाए रखें।[16] 18 अगस्त 1949 को भारत भूटान संधि की धारा–2 के अनुसार भूटान अतंर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की सलाह पर चलता रहा है भारत की सहायता से भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं का सदस्य बना। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश के साथ भी कूटनीतिक संबंध है और कुवैत में भी उसका उप दूतावास है हाँगकाँग और सिंगापुर के साथ भी उसके संबंध है। भारत की ओर से भूटान को आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता दी जाती है भूटान को निर्यात करने में भी भारत सुविधाएं देता है। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद भूटान ने अपनी सुरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया था।[17]

भारतीय दृष्टिकोण से भूटान का सामरिक महत्व

भूटान की लैंड लॉक भौगोलिक स्थिति इसके सामरिक महत्व को स्पष्ट करती है भूटान के उत्तर में तिब्बत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश दक्षिण में असम एवं पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य से लगी सीमा को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भूटान के साथ संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण से भारत भूटान के बीच संबंधों का ताना–बाना काफी पुराना हैं।[18] भारत चीन के मध्य बफर स्टेट होने के बाद भी भूटान भारत के विशेष महत्व रखता है भारत में औपचारिक प्रथा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, सेना और रॉ प्रमुख की पहली विदेश यात्रा भूटान से ही होती है। भूटान भारत के साथ 605 किलोमीटर (376 मील) और चीन के साथ 470

किलोमीटर (292 मील) लम्बी सीमा साझा करता है।[19] दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण परिवहन संसाधनों का अभाव है यहां की नदियां सामरिक महत्व को बढ़ाती है।

भारत भूटान के मध्य व्यापार इन्हीं नदी घाटियों के माध्यम से संपन्न होता है। भारत भूटान के रिश्ते आपसी विश्वास एवं पारस्परिक समझ पर टिके हुए हैं आदर्श पड़ोसी के रूप में दोनों ही राष्ट्र एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारत भूटान संधि 1994 के द्वारा भूटान ने विदेशी मामलों में भारत से परामर्श लेना स्वीकार किया और भारत ने भी सहर्ष भूटान की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। भूटान भी अपने राष्ट्र के चहुमुखी विकास में भारत की भूमिका को नकार नहीं सकता है। भारत भूटान के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है में दोनों देशों के बीच 9000 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार है। भूटान अपने कुल आयात के 80 प्रतिशत से अधिक का आयात भारत से करता है और भूटान के कुल निर्यात का 85 प्रतिशत का निर्यात भारत को किया जाता है। भूटान भारत के लिए एक प्रमुख जल विद्युत स्रोत भी है और भारत के सहयोग से भूटान में विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं संचालित है।[19] भारत भूटान के समक्ष एक विशिष्ट चुनौती प्रस्तुत करता है कि दो बड़े राष्ट्रों के मध्य कैसे सम्बन्ध बनाये रखे जायें। भूटान का भूगोल यह सुनिश्चित करता है कि भारत के साथ अपनी मजबूत पकड़ के लिए व्यूह बनाये रखनी चाहिए।

संबंध बिगड़ने की कोशिश

सन 1947 में भारत से जाते–जाते अंग्रेजों ने भूटान को भी स्वतंत्र किया। अतः भारत ने 18 अगस्त 1949 को भूटान के साथ संधि की और अंग्रेजों के समय की स्थिति को बहाल रखा। इसके साथ भारत सरकार ने भूटान को 32 मील की भूभागीय पट्टी भी, जो उसके साथ दीवान गिरी की एवज में बहुत पहले से चली आ रही थी। भूटान को वापस कर दी इस संधि के अनुसार ही दोनों देशों का यह प्रयास रहा है कि भारत और भूटान के संबंध बिगड़े परंतु भारत का रवैया रचनात्मक रहा है।[20]

अगस्त 1959 को पंडित नेहरू ने लोकसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि भारत सरकार सिक्किम एवं भूटान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इसे दोनों संप्रदायों की क्षेत्रीय अखंडता और भूटान में सिक्किम के खिलाफ किसी भी आक्रमण को भारत के खिलाफ आक्रामकता के रूप में माना जाएगा। आज भी भारत भूटान की सुरक्षा के प्रति वहीं रुख रखता है।[21]

भूटान पर चीन की नजर

चीन की विस्तार वादी नीति से भूटान भी अछूता नहीं रहा है, तिब्बत पर अधिपत्य स्थापित करने के बाद चीन ने ऐसे मानचित्र बनाने शुरू किए जिससे भूटान को तिब्बत का एक बड़ा भूभाग के रूप में दर्शाया गया। भारत द्वारा इसका निरंतर विरोध किया जाता रहा। चीन भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेश करता रहा जबकि भूटान की पूर्वी सीमा चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। 1958 से 1962 तक की अवधि में चीन की सेना ने भूटान की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करता रहा।[22] 1958 में चीन ने एक मानचित्र प्रकाशित करके भूटान की 300 वर्ग मील भूमि पर अपना दावा किया तथा 1966 में डोकलाम चारागाह का अतिक्रमण करके उसे अपना बनाने का दावा पेश किया। इसलिए चीन कई बार घुसपैठ करके भूटानी सीमा का अतिक्रमण किया।[23]

चीन द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ के माध्यम से भूटान पर दबाव डालना था और इस बात को साबित करना था कि भारत चीन सीमा विवाद में भूटान कोई मदद नहीं करेगा। चीन ने 1998 में भूटान चीन सीमा की शांति एवं सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करके भूटान की संप्रभुता एवं स्वतंत्र स्थिति को स्वीकार किया था। इसके बावजूद भी निरन्तर घुसपैठ करता रहा। इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नेतृत्व में आयोजित होने वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन में भूटान के सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन द्वारा उसे प्राप्त होने वाले अतंर्राष्ट्रीय अनुदान को रोकने का असफल प्रयास किया गया वर्ष 1984 से चीन व भूटान के मध्य लगातार वार्तालाप के 24 दौर आयोजित किए गए परंतु कभी भी चीन ने भूटान की पूर्वी सीमा का मुद्दा नहीं उठाया भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश त्वांग जिले के साथ स्पर्श करती है अतः चीन की यह नई चाल भूटान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय है।[24]

निष्कर्ष

इस शोध पत्र से उजागर होता है कि भविष्य में भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि भूटान में चीनी हस्तक्षेप से बढ़ने से भारतीय सम्प्रभुता को हानिकारक साबित हो सकता है। भूटान बफर स्टेट के रूप में भारत के लिए रणनीतिक व सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना है तो भारत और भूटान को अपने द्विपक्षीय संबंधों की नींव को मजबूत करना होगा।

भूटान सीमित आबादी और छोटी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, मगर भारतीय गुणात्मक दृष्टि से काफी महत्व रखता है इसलिए सभी ऐसे मुद्दों पर दोनों देशों को मिलकर विस्तार से विचार करना होगा जो दोनों देशों के विकास शांति सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत एवं चीन के बीच नेपाल एक बफर स्टेट है जिसकी सीमा सिर्फ 2 देशों से लगती है अपनी जरूरतों के लिए नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर है। वर्तमान समय में भारत के लिए नेपाल में चीनी दखल अंदाजी हिमालय पर्वत जैसी बड़ी होती जा रही है। नेपाल में एक दशक से आए राजनीतिक परिवर्तन माओवादियों ताकतों का सत्ता में आना और उनका आकर्षण चीन की तरफ होना भारतीय सुरक्षा खेमे के लिए एक चिंताजनक विषय है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी दूरदर्शी नीति अपनानी होगी अगर भारतीय नजरिए से देखा जाए तो वहां एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत है जो भारत के साथ रिश्तो को बेहतर कर सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मिश्रा, सुरेन्द्र कुमार, रक्षा एवं सुरक्षा,*

2. सिंह, लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ0सं0 477
3. मिश्रा, सुरेन्द्र कुमार, रक्षा एवं सुरक्षा,
4. क्रॉनिकल, (जुलाई 2019) 'अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध व संगठन, पृ0सं0 116
5. http://www.drishtiias.com, 23 मई, 2020
6. http://www.drishtiias.com, 23 मई, 2020
7. दलवी, जे0पी0 (ब्रिगेडियर), 'शर्मनाक हिमालयी चूक', नटराज पब्लिषर्स, देहरादून।
8. नवभारत टाईम्स, 16 जून 2020
9. सिंह, विजेन्द्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, विक्ट्री पब्लिकेषन इलाहाबाद
10. bbchindi.com 23 दिसम्बर 2020
11. दैनिक जागरण 20 नवम्बर 2019 'नेपाल कितना अहम है'।
12. शर्मा, संजय कुमार, (2020) 'भारत–चीन सम्बन्ध बदलता परिदृष्य' एविंस पब पब्लिषिंग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पृ0सं0 169–170
13. बघेल, वीरेन्द्र सिंह, 'भारत का घेरता चीन', आत्माराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, पृ0सं0 107।
14. बघेल, वीरेन्द्र सिंह, 'भारत का घेरता चीन', आत्माराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, पृ0सं0 107।
15. सिंह, लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली
16. शुक्ल, कृष्णानन्द, 'भारत और एशियाई देष', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0सं0 119
17. सिंह, लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, पृ0सं0 477
18. बीबीसी संवाददाता, 24 जुलाई, 2020
19. बीबीसी संवाददाता, 24 जुलाई, 2020
20. सिंह, लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली।
21. वर्ल्ड फोकस–20, जनवरी, 2020, पृ0सं0–76।
22. वर्ल्ड फोकस–20, जनवरी, 2020, पृ0सं0–77।
23. डेली अपडेट्स दृष्टि 'भारत–भूटान और चीन त्रिकोण : अवसर व चुनौतियां, 23 जुलाई 2020।
24. डेली अपडेट्स दृष्टि 'भारत–भूटान और चीन त्रिकोण : अवसर व चुनौतियां, 28 जुलाई 2020।